

प्रेषक,

एन०एस०न०पल०न्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवानो,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: १७ मार्च, २००६

विषय: सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसायटी को बी०फार्मा आदि पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु तहसील देहरादून के ग्राम डांडा खुदानेवाला में कुल ०.७५ है० अतिरिक्त भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

गर्होदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-२२३/१२ए-१४३(२००२-०५)/डी०एल०आर०सी० दिनांक ३१ जनवरी, २००६ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसायटी को बी०फार्मा आदि पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(III) के अन्तर्गत तहसील देहरादून के ग्राम डांडा खुदानेवाला में कुल ०.७५ है० अतिरिक्त भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- १- केंद्रा धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर सविधा में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- २- केंद्रा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- ३- केंद्रा द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उन्हीं प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

(२)

गई हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 को परिणाम लागू होगा।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्थापित किये जाने वाले संस्थान में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत शेअर/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबद्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिरों शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का फल्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलव्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल गण्डल, पीडी।
- 3- सचिव, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- श्री प्रदीप जैन, सचिव, सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसायटी, 5/2 सुभाष रोड, देहरादून।
- 5- निदेशक, एन0आइ0सी0 उत्तरांचल सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(रोहन लाल)
अपर सचिव।